

बिहार की कोसी-मेची लकि परियोजना के नरिमाण का रास्ता साफ

चर्चा में क्यों?

25 दसिंबर, 2022 को मीडिया से मली जानकारी के अनुसार बिहार की अतः महत्त्वाकांक्षी कोसी-मेची लकि परियोजना के नरिमाण का रास्ता साफ हो गया है। इस परियोजना का डीपीआर बनाने के लयि जल संसाधन वभिाग और केंद्रीय जलशक्ति मंत्रालय के तहत जल संसाधन वभिाग की नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुआ है।

प्रमुख बढि

- कोसी-मेची लकि परियोजना के पूरा होने पर राज्य के सीमांचल के चार जिलों में करीब 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में सचिाई सुवधि और बाढ़ से राहत मलिंगी। इनमें पूर्णया, कटहार, कशिनगंज और अररया जिला शामिल हैं।
- इस परियोजना से अररया जिले में करीब 69 हजार हेक्टेयर, पूर्णया जिले में करीब 69 हजार हेक्टेयर, कशिनगंज जिले में 39 हजार हेक्टेयर और कटहार जिले में 35 हजार हेक्टेयर जमीन की सचिाई होगी।
- कोसी-मेची लकि परियोजना से अररया जिले के अंतरगत फारबसिगंज, कुरसाकाटा, सकिटी, पलासी, जोकीहाट एवं अररया प्रखंड को लाभ होगा। वहीं, कशिनगंज जिले के अंतरगत टेढ़ागाछ, दधिलबैंक, बहादुरगंज एवं कोचाधामन प्रखंड को लाभ होगा।
- इसके अलावा पूर्णया जिले के अंतरगत बैसा, अमौर एवं बायसी प्रखंड तथा कटहार जिले के अंतरगत कदवा, डंडखोड़ा, प्राणपुर, मनहारी एवं अमदाबाद प्रखंड लाभान्वति होंगे।
- वदिति है कि कोसी-मेची लकि परियोजना का काम शुरू करने के लयि पहले ही राज्य कैबनेट से मंजूरी मलि चुकी है। मई 2022 में ही राज्य सरकार ने डीपीआर गठन, सर्वेक्षण और अन्वेषण कार्य के लयि करीब दो करोड़ 78 लाख रुपए की प्रशासनिक और खर्च की सवीकृति दे दी थी।
- राज्य सरकार द्वारा 90 फीसदी केंद्रांश की हो रही मांग तथा केंद्र सरकार द्वारा इस परियोजना को राष्ट्रीय परियोजना में शामिल करते हुए, इसके लयि केंद्रांश 60 फीसदी और राज्यांश 40 फीसदी के रूप में बजटीय प्रावधान की मंजूरी दी गई है।
- हालांकि, राज्य सरकार की ओर से कोसी-मेची लकि परियोजना के लयि भी मध्य प्रदेश की केन-बेतवा लकि परियोजना की तरज़ पर केंद्रांश 90 फीसदी और राज्यांश 10 फीसदी बजटीय प्रावधान की मांग जारी है।
- इस परियोजना के अंतरगत कुल लगभग 1397 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता है, जसिमें से 632 हेक्टेयर भूमि पूर्व से अधगृहीत है, जबकि 765 हेक्टेयर नजि भूमि का अधग्रहण कया जाना है।